सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गरमाया आरक्षण का मुद्दा

कांग्रेस बोली ▶ वह नियुक्तियों और पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत

पार्टी ने कहा, भाजपा शासन के दौरान एससी, एसटी का अधिकार खतरे में है

नई दिल्ली, एजेंसियां : आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से सियासी माहौल गरमा गया है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा है कि वह नियुक्तियों और पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत है। कांग्रेस ने भाजपा से सरकारी नौकरियों और पदोन्नति में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण पर अपना रुख साफ करने के लिए कहा। पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन के दौरान एससी और एसटी का अधिकार खतरे में है।

रविवार को पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक ने कहा कि पार्टी संसद के अंदर और बाहर इस मुद्दे को उठाएगी। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस का मानना है कि सरकारी पदों पर एससी, एसटी समुदाय की नियुक्ति सरकारों के विवेक पर नहीं है, बल्कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है।'

मुकुल वासनिक फाइल फोटो

लोजपा ने भी फैसले पर उठाया सवाल

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार में भाजपा की सहयोगी लोजपा ने भी सवाल उठाया है। पार्टी ने केंद्र सरकार से कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए कि पिछड़ी जातियों के अलावा अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण का लाभ उसी तरह से मिलता रहे, जैसे दशकों से मिल रहा है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अपनी पार्टी की असहमति व्यक्त की कि राज्य सरकारें इन समुदायों को सरकारी नौकरी या पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं।

चिराग पासवान फाइल फोटो

यह है सुप्रीम कोर्ट का फैसला

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकारें नियुक्तियों में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं तथा पदोन्नति में आरक्षण का दावा करने का कोई मूल अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता की पीठ ने हाल में दिए गए फैसले में कहा कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य सरकारें आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं। ऐसा कोई मूल अधिकार नहीं है, जिसके तहत कोई व्यक्ति पदोन्नति में आरक्षण का दावा करे। पीठ ने अपने फैसले में कहा, 'न्यायालय राज्य सरकार को आरक्षण उपलब्ध कराने का निर्देश देने के लिए कोई परमादेश नहीं जारी कर सकता है।' उत्तराखंड सरकार के पांच सितंबर, 2012 के फैसले को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी।

उत्तराखंड ने लिया स्टैंड, राज्य पदोन्नति में आरक्षण देने को बाध्य नहीं : उदित राज

कांग्रेस के प्रवक्ता उदित राज ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उत्तराखंड सरकार ने स्टैंड लिया है कि राज्य सरकारें पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं। केंद्र पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था, जिसमें कहा गया था कि पदोन्नति पर आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए। केंद्र अब भी उच्चतम न्यायालय में उस मामले की पैरवी कर रही है।

उदित राज फाइल फोटो

केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करे या फिर संविधान में संशोधन करे : मल्लिकार्जुन खड़गे

कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की कि केंद्र सरकार या तो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करे या आरक्षण को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन करे। खड़गे ने बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि नौकरियों और प्रोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। इस फैसले ने हाशिए के समुदायों को चिंतित किया है। हम इसके खिलाफ संसद के भीतर और बाहर विरोध करेंगे। भाजपा और आरएसएस लंबे समय से आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।

मल्लिकार्जुन खड़गे

राहुल को पॉलिटिकल प्ले स्कूल भेजें सोनिया गांधी : नकवी

नईदुनिया, इंदौर

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राजनीति में शालीनता होनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, यह सीखना चाहिए। राहुल गांधी के डंडे वाले बयान को देखकर लगा कि उन्होंने यह सामान्य स्थिति में तो नहीं बोला होगा। नकवी बोले, 'मैं यह तो नहीं कह सकता हूं कि उन्हें नशा मुक्ति केंद्र भेजने की जरूरत है, लेकिन सोनिया गांधी को मेरी सलाह है कि राहुल गांधी को पॉलिटिकल प्ले स्कूल में भेज दें।'

यहां अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा आयोजित 'हुनर हाट' का शुभारंभ करने आए नकवी पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली चुनाव पर कहा, 'हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। शाहीनबाग हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं था क्योंकि हम गोली नहीं, बोली पर यकीन करते हैं। शाहीनबाग में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें गुमराह किया जा रहा है। हमने उन्हें न तो बैठने के लिए कहा था और न प्रदर्शन समाप्त करने के लिए दबाव डालेंगे।'

डरने की जरूरत नहीं : नकवी ने कहा कि कांग्रेस सीएए के मुद्दे पर लोगों को भड़का कर जनगणना में हिस्सा नहीं लेने देना चाहती है। ऐसा कर वह लोगों को उनके अधिकार से वंचित कर रही है। जो अवैध घुसपैठिए हैं, उन्हें डरने की जरूरत है। भारतीय नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकारों द्वारा सीएए का विरोध जायज नहीं है। नागरिकता केंद्र का विषय है, राज्यों का नहीं। कोई भी राज्य केंद्र के कानून को लागू करने से इनकार नहीं कर सकता।

मप्र के इंदौर शहर में रविवार से शुरू हुए हुनर हाट में झूला झूलते राज्यपाल लालजी टंडन और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। नईदुनिया

राज्यपाल बोले, बाजारवाद से खत्म हो रहा दस्तकारों का हुनर : राज्यपाल लालजी टंडन और केंद्रीय मंत्री नकवी ने विजय नगर चौराहे पर आयोजित 'हुनर हाट' का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने कहा, आज यह कहना फैशन बन गया है कि देश में नौकरियां नहीं हैं लेकिन नौकरियां कितनी मिलेंगी? 130 करोड़ लोगों को नौकरी चाहिए, पर हजारों साल में इस देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सब नौकर हो गए और आगे भी नहीं होगा। हमारे गांवों में आज भी नौकरी को तीसरे नंबर पर रखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है- 'उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निपट चाकरी और भीख निदान।'

दुश्मन के छक्के छुड़ाएगी नई मिसाइल 'प्रनाश'

नई दिल्ली, एएनआइ : भारत एक नई और उन्नत श्रेणी की मिसाइल विकसित कर रहा है, जिसे 'प्रनाश' नाम दिया गया है।। इस मिसाइल से 200 किलोमीटर दूर तक निशाना साधा जा सकेगा। इससे थल और वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा।

रक्षा अधिकारियों ने कहा, 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) 200 किलोमीटर तक मार करने वाली प्रनाश मिसाइल को विकसित कर रहा है। यह मिसाइल पारंपरिक वारहेड से लैस होगी।'अधिकारियों के मुताबिक 'प्रनाश' मिसाइल 150 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली 'प्रहार' की उन्नत संस्करण है। प्रहार मिसाइल भी ठोस इंधन की सतह से सतह तक मार करने में सक्षम कम दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। डीआरडीओ ने ही इसे भी विकसित किया है।

सतह से सतह तक मार करने में सक्षम 'प्रनाश' भी एकल चरण ठोस इंधन की बैलिस्टिक मिसाइल है। सेना और वायु सेना द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाएगा। प्रनाश मिसाइल का प्रयोग किसी भी सामरिक और रणनीतिक लक्ष्यों को भेदने के लिए किया जा सकेगा। अधिकारियों ने उम्मीद जताई

▶ सेना और वायुसेना की बढ़ेगी ताकत, दो सौ किलोमीटर तक होगी मारक क्षमता

प्रहार मिसाइल की तर्ज पर विकसित होगी 'प्रनाश'(फाइल फोटो)। एएनआइ

कि एक-दो वर्ष के भीतर इसका परीक्षण कर लिया जाएगा। नई मिसाइल से भारत की सामरिक क्षमता को मजबूत होगी ही। वह अपने मित्र राष्ट्रों को इसका निर्यात भी कर सकेगा, क्योंकि इसकी मारक क्षमता मिसाइल की बिक्री के लिए तय अंतरराष्ट्रीय मानकों के भीतर ही है। उल्लेखनीय है कि भारत अपने मिसाइल कार्यक्रम को बहुत अधिक तवज्जो देता है। देश की वैज्ञानिक इस संबंध में नित नए प्रयोग करते रहते हैं।

बाबा विश्वनाथ के भक्त राजपक्षे

भारत दौरे पर आए श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे रविवार को वाराणसी पहुंचे और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। प्रेट्र

भारतीय नागरिकता मिले, तो आधा बांग्लादेश खाली हो जाएगा : रेड्डी

हैदराबाद, प्रेट्र : केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि यदि बांग्लादेशी लोगों को भारत की नागरिकता का आश्वासन दिया जाए, तो आधा बांग्लादेश खाली हो जाएगा। रविवार को संत रविदास जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को यह साबित करने की चुनौती दी कि किस तरह नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) 130 करोड़ भारतीयों के खिलाफ है?

गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने पूछा कि यहां आए बांग्लादेशियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? चंद्रशेखर राव? या राहुल गांधी? उन्होंने कहा कि वे घुसपैठियों के लिए नागरिकता की मांग कर रहे हैं। यदि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) में देश के 130 करोड़ नागरिकों के खिलाफ कुछ है, तो भारत सरकार इसकी समीक्षा करने के लिए तैयार है, लेकिन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुस्लिमों को इसके तहत नागरिकता नहीं दी जाएगी। यह उल्लेख करते हुए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने के लिए सीएए लाया गया है, जी किशन रेड्डी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल उन देशों के मुस्लिमों को भी नागरिकता देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति पर वोट बैंक की राजनीति में शामिल रहने का आरोप भी लगाया।

उन्होंने कहा कि शरणार्थियों और घुसपैठियों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। लेकिन, कांग्रेस जैसी पार्टी पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए मुस्लिमों को भी नागरिकता देने की मांग कर रही है। गृह राज्यमंत्री रेड्डी के अनुसार, कुछ शरणार्थी पिछले 40 वर्षों से बिना किसी सुविधा और दस्तावेज, मसलन मतदाता पहचान पत्र, आधार और राशन कार्ड के भारत में रह रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल नागरिकता संशोधन कानून का खुलकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में तमाम बार स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है फिर भी देश के विभिन्न राज्यों में विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है।

▶ मंत्री ने पूछा, यहां आए बांग्लादेश के लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा

▶ शरणार्थियों और घुसपैठियों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता

हैदराबाद में रविवार को संत रविदास जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी। एएनआइ

बिहार में लोजपा के स्टैंड से जदयू कोटे के मंत्रियों ने ली इत्मीनान की सांस

भुवनेश्वर वात्स्यायन, पटना

▶ पारंपरिक रूप से कई सीटों पर रही है लोजपा की दावेदारी

▶ पासवान की पार्टी के कुछ पुराने दिग्गजों के नाराज होने का संकट

21 सीटों पर पिछली बार था सीधा मुकाबला

पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसी 21 सीटें थीं, जिन पर जदयू और लोजपा के प्रत्याशी के बीच सीधा मुकाबला था। लोजपा एनडीए का हिस्सा था और जदयू महागठबंधन को नेतृत्व दे रहा था। बाबूबरही, त्रिवेणीगंज, ठाकुरगंज, आलमनगर, सोनबरसा, कुशेश्वर स्थान, हायाघाट, कुचायकोट, बरहरिया, कल्याणपुर, वारिसनगर, चेरिया बरियारपुर, अस्थावां, हरनौत, सिमरी बख्तियारपुर, गौराबौराम, बेल्दौर, नाथनगर, जमालपुर, हरनौत व रफीगंज में लोजपा-जदयू के बीच आमने-सामने का मुकाबला था।

इस बार 2015 के विधानसभा चुनाव से अलग समीकरण होने की वजह से राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों में अपनी सीट को लेकर संशय की स्थिति थी। दरअसल, ऐसी कई सीट हैं, जिन पर पारंपरिक रूप से लोजपा की दावेदारी रही है पर लोजपा के हालिया स्टैंड से जदयू कोटे के कई मंत्रियों को अपनी सीट को लेकर इत्मीनान हो गया है। लोजपा ने सार्वजनिक रूप से यह एलान कर दिया है कि जदयू की सीटिंग सीट यानी जहां से जदयू के प्रत्याशी को 2015 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई थी, उन सीटों पर लोजपा अपनी दावेदारी नहीं करेगी। इस फैसले से लोजपा के भीतर ही कुछ लोगों के नाराज होने की संभावना है, क्योंकि इनमें कई ऐसी सीटें हैं, जिस पर लोजपा के पुराने दिग्गज नियमित रूप से चुनावी दंगल में उतरते रहे हैं।

कुछ मंत्रियों को अब अपनी सीट को लेकर संशय नहीं : समस्तीपुर जिले की कल्याणपुर सीट पर लोजपा पारंपरिक रूप से अपना उम्मीदवार देती रही है। पिछली बार रामविलास पासवान के भतीजे प्रिंस राज वहां से चुनाव लड़े थे। तब जदयू के महेश्वर हजारी ने उन्हें हराया था। महेश्वर हजारी अभी मंत्री हैं। आलमनगर में जदयू के नरेंद्र नारायण यादव का सीधा मुकाबला लोजपा प्रत्याशी से था। नरेंद्र नारायण यादव को जीत मिली और वह मंत्री हैं। गौराबौराम विधानसभा सीट से लोजपा प्रत्याशी को हराकर जदयू के मदन सहनी मंत्री बने। नौशाद आलम ने लोजपा प्रत्याशी को हराया और मंत्री बने। पूर्व में चेरियाबरियारपुर से जीतीं मंजू वर्मा और सिमरीबख्तियारपुर से जीते दिनेशचंद्र यादव भी इसी श्रेणी में थे। जमालपुर से लोजपा प्रत्याशी को हराकर शैलेश कुमार मंत्री हैं। लोजपा के स्टैंड से उसके अपने ही कुनबे में कुछ के बिदकने का संकट है। इनमें कुचायकोट की सीट से लड़ने वाले काली पांडेय और चेरिया बरियारपुर से लड़ने वाले अनिल कुमार चौधरी का नाम लिया जा सकता है।

भारत का विभाजन होने की मुझे खुशी : नटवर सिंह

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता और पूर्व विदेश मंत्री के.नटवर सिंह ने कहा है कि 'भारत का विभाजन होने की मुझे खुशी है।...अन्यथा मुस्लिम लीग देश को कामकाज करने नहीं देती। इससे देश में और 'डायरेक्ट एक्शन डेज' (यानी 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग की ओर से घोषित कलकत्ता दंगे) होते।'

राज्यसभा सदस्य एमजे अकबर की नई किताब 'गांधीज हिंदूइज्म : द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम' का विमोचन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया। इस अवसर पर रविवार को प्रणब ने कहा, महात्मा गांधी अपने सार्वजनिक जीवन में हमेशा भारत की एकता के लिए लड़े। उन्होंने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया कि धार्मिक आधार पर देश को बांटा जा सकता है।

नटवर सिंह ने कहा, वह भारत का विभाजन होने से खुश हैं, क्योंकि अगर बंटवारा नहीं होता तो और भी डायरेक्ट एक्शन (हिंदुओं का कत्लेआम) होते। ऐसा पहली बार जिन्ना (मुहम्मद अली जिन्ना) के समय में 16 अगस्त (1946) को हुआ था, जब कोलकाता (तब कलकत्ता) में हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। और

▶ कांग्रेस नेता बोले- अन्यथा मुस्लिम लीग देश को कामकाज करने नहीं देती

▶ प्रणव बोले-गांधी जी ने धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन स्वीकार नहीं किया

नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद एमजे अकबर की किताब गांधी हिंदुइज्म : द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाह इस्लाम की लांचिंग के मौके पर (बाएं से) वरिष्ठ कांग्रेस नेता नटवर सिंह, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। ट्विटर से

उसके जवाब में बिहार में हजारों मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता था कि मुस्लिम लीग ने देश को कामकाज करने ही नहीं दिया होता।

ज्ञात हो, मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों से अलग देश बनाने के लिए 'डायरेक्ट एक्शन' का आह्वान किया था। 16 अगस्त, 1946 को '1946 की कलकत्ता किलिंग' या 'डायरेक्ट एक्शन' के नाम से जाना जाता है। तब ब्रिटिश काल के बंगाल में हिंदू-मुस्लिम दंगे हो गए थे।

नटवर सिंह ने इस घटना में मुस्लिम लीग की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि 2 सितंबर, 1946 को अंतरिम भारत सरकार का गठन हुआ था। तभी मुस्लिम लीग ने परिषद के उपाध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू की कैबिनेट में शामिल होने से पहले-पहल इन्कार कर दिया था। लेकिन मुस्लिम लीग बाद में कैबिनेट में सिर्फ इसलिए शामिल हो गई ताकि कैबिनेट के सभी प्रस्तावों का विरोध कर सके।

88 वर्षीय नटवर सिंह ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि आप बड़े पैमाने पर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर भारत का विभाजन नहीं होता तो मुस्लिम लीग ने सब कुछ एकदम दुश्वार कर दिया होता। सिंह ने गांधी और जिन्ना को दो बेहद महान और कठिन व्यक्ति बताया। उनके साथ रह पाना असंभव था। चूंकि गांधी जी के जीवन के मापदंड बेहद ऊंचे थे और मैं उस तक पहुंच पाने में असमर्थ रहता। जबकि जिन्ना बेहद कठोर व्यक्तित्व वाले थे। वह मानते हैं कि गांधी ने सी.राजगोपालाचारी को भारत का आखिरी गवर्नर जनरल बनाने के लिए जिन्ना की खुशामद की थी। नटवर सिंह ने दावा किया कि दर्शकों में वही ऐसे थे जिसने गांधी को खून से लतपथ देखा था।

सिस्टर सिटीज

वाराणसी इस परियोजना पर तेजी से काम करने में अमृतसर की मदद करेगा, अहमदाबाद अब इस परियोजना को लागू करने में चंडीगढ़ का सहायक होगा

पिछड़े शहरों की मदद करेंगे 20 स्मार्ट शहर

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में चयनित सौ स्मार्ट सिटी परियोजना में कुछ शहर पीछे चल रहे हैं। लिहाजा, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी इस परियोजना पर तेजी से काम करने में अमृतसर की मदद करेगा। वहीं, गुजरात का शहर अहमदाबाद अब इस परियोजना को लागू करने में चंडीगढ़ की मदद करेगा।

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सौ स्मार्ट सिटीज में से सबसे अच्छा काम करने वाले बीस शहरों के साथ सबसे खराब काम करने वाले शहरों के जोड़े बना दिए हैं। इन जोड़ीदार शहरों को 'सिस्टर सिटीज' का नाम दिया गया है।

आंतरिक रैंकिंग के अनुसार अहमदाबाद (नंबर एक), नागपुर, तिरुप्पुर, रांची, भोपाल, सूरत, कानपुर, इंदौर, विशाखापत्तनम, वेल्लोर, वडोदरा, नासिक, आगरा, वाराणसी, दावनगीरी, कोटा, पुणे, उदयपुर, देहरादून और अमरावती 20 बेस्ट स्मार्ट सिटी बनने की दिशा में अच्छा काम करने वाले शहरों में शुमार हैं। एक अधिकारी ने बताया कि 20-20 फार्मूले के तहत रांची की शिमला के साथ और पुणे की धर्मशाला के साथ जोड़ी बनाई गई है। सर्वश्रेष्ठ शहरों में शुमार रहे रांची और पुणे क्रमशः शिमला और धर्मशाला को गाइड करेंगे और बेहतर कामकाज करने में विचारों का आदान-प्रदान करके उनकी मदद करेंगे।

मंत्रालय ने ऐसा करने के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि 20 फरवरी से पहले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 20 शहर और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 20 शहर इसी तरह से जोड़ी बनाकर एमओयू पर हस्ताक्षर कर लें। इन शहरों की जोड़ी उनकी क्षेत्रीय समानता और संस्कृति के आधार पर की गई है। उदाहरण के लिए धर्मनगरी वाराणसी की जोड़ी अमृतसर के साथ बनाई गई है। ताकि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उनके कामकाज में सुधार आए। विशाखापत्तनम और सूरत दियू और शरनपुर की मदद करेंगे। जबकि भोपाल अपने विचार मिजोरम की राजधानी एजल से साझा करेंगे। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह शहर सौ दिनों की चुनौती का सामना करेंगे।

केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 2015 में की थी। इसका मकसद शहर का सभी क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करने के साथ ही नागरिकों के लिए आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराना है। इस मिशन के तहत स्मार्ट की 5151 परियोजनाओं का चयन किया गया है। इनकी लागत 2,05,018 करोड़ रुपये होगी।

20 बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों में अहमदाबाद और कानपुर शामिल

5151 परियोजनाओं का चयन किया गया है मिशन स्मार्ट के तहत

2015 में केंद्र सरकार ने शुरू किया था स्मार्ट सिटी मिशन

प्रतीकात्मक फोटो

कबीर और रविदास ने सिखाया प्रत्येक का सम्मान करना : प्रियंका

जागरण संवाददाता, वाराणसी : संत रविदास की जयंती पर रविवार को उनकी जन्मस्थली वाराणसी स्थित सीर गोवर्धनपुर में आयोजित समारोह में पहुंचीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दर्शन-पूजन संग मंदिर में मत्था टेका और परिक्रमा की। अमृतवाणी पर पुष्पांजलि दी और लंगर-प्रसाद ग्रहण किया। सत्संग पंडाल में देश-विदेश से आए रैदासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संत कबीरदास व संत रविदास ने हमें प्रत्येक की इज्जत करना सिखाया।

प्रियंका ने कहा, इंसान में भगवान देखने की हमारी सोच रही है। मानव को जाति या धर्म में बांटकर नहीं एक इंसान के रूप में देखना चाहिए। संत रविदास कहते थे कि राम-रहीम एक हैं। हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं, हमें यह बात सीखनी चाहिए। उन्होंने बेगमपुरा का सपना देखा था, जहां कोई भेदभाव न हो। हमारे संविधान में इसे बनाए रखने की कोशिश की गई।

कह के रहेंगे माधव जोशी